RNI No.UTTHIN/2015/68784 www.twnews.in हिन्दी मासिक पत्रिका

टाईम विटनेस

सभी देश व प्रदेशवासियों को दिपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं ।

वर्ष :11 अंक :03 अक्टूबर 2025 मूल्य : रु 15/-

क्योंकि हम उठायेंगे आपकी आवाज!

त्रिवेंद्र की धमक से धामी सरकार बैकफुट पर

पहुंचे युवाओं के द्वार!

समस्त प्रदेश व देशवासियों
को
दीपावली
गोवर्धन पूजा
व भैया दूज
की हार्दिक
शुभकामनाएं
शिवानी बंसल
पूव पार्षद , वार्ड न0 59
संजीत बंसल (घोली)
पार्षद , वार्ड न0 59

समस्त
प्रदेशवासियों
को
दीपावली
गोवर्धन पूजा व भैया दूज
की हार्दिक शुभकामनाएं
समीर पुण्डीर
पूर्व ग्राम प्रधान चालंग,
न्यायपंचायत गुजराड़ा

समस्त प्रदेश व
देशवासियों को
दीपावली
गोवर्धन पूजा
व भैया दूज
की हार्दिक
शुभकामनाएं
विक्रम सिंह इंद्रवाल
समाज सेवी एवं युवा बीजेपी नेता
मंडल मंत्री, मसूरी विधानसभा

समस्त प्रदेशवासियों को
दीपावली
गोवर्धन पूजा
व भाई दूज
की हार्दिक
शुभकामनाएं
महिमा पुण्डीर
पार्षद, वार्ड 4
सुधीर पुण्डीर

सभी देश व
प्रदेशवासियों को
दीपावली
गोवर्धन पूजा व भैया दूज
की हार्दिक शुभकामनाएं
हाजी सलीम अहमद
पू. प्रदेश मंत्री, अ०स० मो०, भाजपा, उत्तराखण्ड
प्रदेश सह प्रभारी , सूफी समाज संवाद उत्तराखण्ड

समस्तप्रदेशवासियों को
दीपावली
गोवर्धन पूजा व भैया दूज
की हार्दिक शुभकामनाएं
इरशाद अली
पूर्व ग्राम प्रधान, मेहूवाला माफी
वरिष्ठ भाजपा नेता, उत्तराखण्ड

PRAYAG IAS Academy

Uttarakhand's Leading Institute for
IAS/PCS, PCS (J)
Prayag IAS College Maan Singh Waala,
Dehradun, Ph. No. 0135-2744550

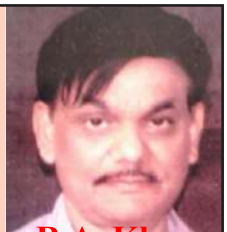

R.A. Khan
Director

आरएनआई संख्याः UTTHIN/2015/68784

टाईम विटनेस

मासिक पत्रिका वर्षः 11 अंक : 03

अक्टूबर 2025

सह संरक्षक	डॉ. संजय गांधी
विशेष सलाहकार	विजय खण्डूड़ी
कानूनी सलाहकार	मनमोहन कण्डवाल (एडवोकेट)
संपादक	अफरोज़ खाँ
सह संपादक	अशोक रावत
उत्तर प्रदेश प्रभारी	शादाब अली
उत्तराखण्ड ब्यूरो चीफ	इफ्तेखार अंसारी
पछवादून प्रभारी	संजय कुमार
व्यवस्थापक	मेघराज सिंह राठौर
ब्यूरो चीफ, उन्नाव	अनवार अहमद
संवाददाता	बाबू हसन

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अफरोज खाँ द्वारा आईशा प्रिन्टिंग प्रेस, चुक्खुवाला, देहरादून से मुद्रित कराकर, नियर रिवरेन पब्लिक स्कूल, ब्राह्मणवाला, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड से प्रकाशित।

संपादक अफरोज खाँ

पत्रिका से संबंधित किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला- देहरादून ही मान्य होगा।

अन्दर के पृष्ठ में

12 **विचारधारा से सत्ता तक**

16 **सांप्रदायिक हिंसा और ध्रुवीकरण का नया बहाना**

20 **उत्तरप्रदेश में मायावती की नई चुनौती**

क्षेत्रीय कार्यालय टाईम विटनेस

68 माजरा सहारनपुर रोड नियर होटल सुंदर पैलेस, देहरादून, उत्तराखण्ड।

मो0 7409293012, 9084366323

ई-मेलः timewitness2015@gmail.com, afrojkhan78600@gmail.com

नोटः जरूरी नहीं कि लेखक के लिखे लेख से सम्पादक सहमत हो, एवं सभी पद परिवर्तनीय है व सभी सदस्य अवैतनिक है।

पेपर लीक प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य को केवल घोषणाओं की नहीं, बल्कि सच्चे राजनीतिक साहस की आवश्यकता है। यदि सरकार ने इससे सबक नहीं लिया, तो यह घोटाला ''उत्तराखण्ड का व्यापम'' साबित हो सकता है- एक ऐसा दाग जो वर्षों तक मिट नहीं पाएगा।

युवाओं में असंतोष की भावना

उत्तराखण्ड का युवा आज गहरे असंतोष में है। यह असंतोष केवल बेरोजगारी या सीमित अवसरों की वजह से नहीं, बल्कि उस टूटे हुए विश्वास से उपजा है जो उसने शासन और व्यवस्था पर किया था। राज्य निर्माण को दो दशक से अधिक हो चुके हैं, लेकिन युवाओं को अब यह महसूस होने लगा है कि उनके संघर्ष, उम्मीदें और परिश्रम कहीं न कहीं सत्ता के शोर में दब गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कभी युवा नेतृत्व की पहचान थे, अब उन्हीं युवाओं के सवालों के घेरे में हैं। यह विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि उस तंत्र के विरुद्ध है, जिसने योग्यता के स्थान पर पैसे और सिफारिश को प्राथमिकता दी है। यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण ने युवाओं के भीतर छिपे आक्रोश को सार्वजनिक कर दिया। 2025 में जब यह पेपर लीक प्रकरण दुबारा सामने आया, तो उन हजारों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया जिन्होंने वर्षों तक परीक्षाओं की तैयारी की थी। जो प्रश्नपत्र उनके भविष्य का आधार होना था, वह भ्रष्टाचार के दलदल में बिक गया। यह सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि विश्वास की हार थी। युवाओं को लगा कि उनकी योग्यता की कीमत बाजार तय कर रहा है। जब न्याय की उम्मीद जागी, तो जांच की रफ्तार ने फिर से भरोसा तोड़ दिया। सरकार ने तत्काल एसटीएफ गठित कर जांच शुरू की, गिरफ्तारियाँ हुईं, और आरोपियों के नाम उजागर हुए। अदालतों में तारीखें बढ़ती रहीं, चार्जशीट दाखिल होने में विलंब हुआ, और कई मामलों में सुनवाई की रफ्तार सुस्त रही। इस बीच, हजारों युवाओं ने अपनी तैयारी, अपनी उम्मीदें और अपनी उम्र का कीमती समय खो दिया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में कई बार कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति "जीरो टॉलरेंस" नीति पर चलती है, लेकिन युवाओं के लिए यह नारा अब एक खोखला जुमला बन गया है। ज़मीनी स्तर पर उन्हें लगता है कि यह नीति केवल भाषणों तक सीमित है। जिन पर गंभीर आरोप लगे, वे कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आ गए, कुछ के मामलों में राजनीतिक प्रभाव साफ दिखाई दिया। इस सबने यह संदेश दिया कि न्याय की दिशा भी सत्ता की मंशा पर निर्भर है। उत्तराखण्ड का युवा अब पुरानी पीढ़ियों की तरह चुप नहीं रहता। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय है, हर सरकारी बयान की समीक्षा करता है, और सवाल उठाने से पीछे नहीं हटता। यही कारण है कि पेपर लीक प्रकरण केवल एक घोटाले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर और श्रीनगर जैसे शहरों में अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, नारे लगाए– "पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराओ", "दोषियों को सजा दो।" लेकिन जब इन आवाजों को प्रशासनिक सख्ती से दबाने की कोशिश की गई, तो यह असंतोष आक्रोश में बदल गया। पेपर लीक प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य को केवल घोषणाओं की नहीं, बल्कि सच्चे राजनीतिक साहस की आवश्यकता है। यदि सरकार ने इससे सबक नहीं लिया, तो यह घोटाला "उत्तराखण्ड का व्यापम" साबित हो सकता है– एक ऐसा दाग जो वर्षों तक मिट नहीं पाएगा। आज उत्तराखण्ड का युवा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा है जिसने उसकी मेहनत की कीमत घटा दी। यह असंतोष एक चेतावनी है कि यदि इसे संवाद और सुधार से नहीं संभाला गया, तो यही युवा आने वाले चुनावों में बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सरकार के पास अभी समय है, वह चाहे तो इस आक्रोश को अवसर में बदल सकती है, या फिर इसे अपने पतन की कहानी बनने दे सकती है। अब सवाल केवल इतना है कि क्या उत्तराखण्ड की राजनीति अपने युवाओं का विश्वास दोबारा जीत पाएगी, या इतिहास में यह दौर "टूटी उम्मीदों का समय" बनकर दर्ज होगा?

आजम अखिलेश मुलाकात

सितारों से आगे जहां और भी है

शिब्ली रामपुरी
लेखक

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आज़म खान की मुलाकात पर सबकी नजर टिकी थी और आखिरकार अखिलेश यादव रामपुर में आजम खान से मिलने पहुंचे दोनों की काफी खुशनुमा माहौल में मुलाकात हुई. जिस बात की अक्सर चर्चा रहती है उसी को लेकर वहां मीडिया ने सवाल भी कर लिया कि आजम खान तो आपसे नाराज थे इस पर अखिलेश यादव की बजाय आजम खान ने जवाब देते हुए कहा आपको यह सूचना कहां से मिल गई?

आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात करने से पहले कुछ शर्ते भी मीडिया के जरिए सामने रखी थी जिसको अखिलेश यादव पूरी करते नजर आए. इनमें एक यह थी कि रामपुर से जो सांसद बने हैं वह अखिलेश यादव के साथ नहीं आने चाहिए तो अखिलेश यादव ने ऐसा ही किया. जिससे समाजवादी पार्टी में मौजूदा वक्त में भी आजम खान के रुतबे का पता चलता है वैसे तो यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आजम खान से मिलने इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव तकरीबन करीब आ रहा है और कहीं मुस्लिम वोटर्स उनसे नाराज ना हो जाएं इसलिए उन्होंने आजम खान से मुलाकात की है। इस मुलाकात पर यूपी में मंत्री ओपी राजभर का बयान भी सामने आया है। बहरहाल आजम खान की मुलाकात अखिलेश यादव से हो गई है और खुद अखिलेश यादव आजम खान से मिलने उनके निवास पर पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि वह आज भी आजम खान की अहमियत को समझते हैं. अखिलेश और आजम खान की मुलाकात पर ज्यादा कुछ भी फिलहाल राजनीतिक तौर पर नहीं कहा जा सकता लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सितारों से आगे जहां और भी है।

त्रिवेंद्र की धमक से धामी सरकार बैकफुट पर पहुंचे युवाओं के द्वार!

अशोक रावत,
सह संपादक

उत्तराखण्ड की सियासी गलियारों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, राजनीति और युवाओं के बीच एक नई हलचल है। उत्तराखण्ड की राजनीति में फिर एक पुराना नाम गूंजने लगा है, पूर्व मुख्यमंत्र त्रिवेंद्र सिंह रावत। जिन्हें 2021 में अचानक कुर्सी से हटाया गया था, अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं।

उनके हालिया बयान एवं एकदम से सक्रिय होना और युवाओं के बीच उनकी बढ़ती चर्चा ने राज्य की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। कहा जा रहा है कि "त्रिवेंद्र की धमक" से धामी सरकार बैकफुट पर आ गई है। और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य पेपर लीक जैसे घोटालों से हिल चुका है। राज्य की स्थापना के बाद जनता ने लगातार उम्मीद की कि 'छोटा राज्य' बेहतर शासन देगा। लेकिन पिछले दो दशकों में सत्ता के बार–बार बदलते चेहरे, भ्रष्टाचार के आरोप, और पेपर लीक की घटनाओं ने जनता के भरोसे को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने खुद को 'युवा मुख्यमंत्री' के रूप में पेश

किया। लेकिन विडंबना यह है कि उनके कार्यकाल में ही युवाओं का गुस्सा सबसे अधिक फूटा है।

राज्य में भाजपा शासित सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में हैं और सीएम धामी अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने कि तरफ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन धामी सरकार इस दौरान कई बार अपने ही नेताओं और विधायकों के कारण असहज हुई है। इस पक्ति में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पीछे नहीं हैं। टीएसआर के बयानों से कई बार धामी सरकार की फजीहत हुई है, चाहे राज्य में अवैध खनन का मुद्दा हो अथवा पेपर लीक का मामला। त्रिवेन्द्र बेबाक और कड़क अंदाज में अपनी सरकार को घेरते दिखे। उनके बयानों से उत्तराखंड में सियासी राजनीतिक हलचल शुरू हो जाती है। कुछ महीने पहले संसद में बोलते हुए रावत ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार सहित पूरे उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उत्तराखंड के खनन सचिव आईएएस अधिकारी ब्रजेश कुमार संत ने उनके आरोपों का खंडन किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रावत ने यह कहकर विवाद को और हवा दे दी कि "शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते"। लेकिन इसी बीच मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा कि उनका बयान किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं था। टीएसआर का कहना है कि उन्होंने पार्टी को अपने खून और जवानी से सींचा है। उन्होंने कहा, मैं क्यों चाहूंगा कि सरकार अस्थिर हो?

इस घटना ने एक बार फिर राज्य भाजपा इकाई में मतभेदों को उजागर कर दिया है और उत्तराखंड भाजपा के सूत्रों के अनुसार, जैसे ही यह मामला सामने आया, केंद्रीय पार्टी नेतृत्व ने राज्य इकाई से तुरंत इस मामले की जाँच करने को कहा। हालांकि, राज्य भाजपा नेताओं में रावत के विचारों का समर्थन करने वालों और उनकी आलोचना करने वालों के बीच मतभेद हैं। उदाहरण के लिए, लालकुआं के विधायक नवीन चंद्र ने रावत का बचाव किया और खनन विभाग के कामकाज की आलोचना की, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का समर्थन किया।

मीडिया से बात करते हुए भट्ट ने बताया कि खनन राजस्व में गुणात्मक सुधार हुआ है और कहा कि इससे पता चलता है कि राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगा है। दूसरी ओर, विधायक किशोर उपाध्याय ने ऐसे आरोप लगाने से मना किया और लोगों को अपने काम से काम रखने की सलाह दी। "चुनाव बेशक लगभग एक साल दूर हैं, लेकिन राजनीति कभी नहीं रुकती। ऐसे कई उदाहरण हैं जब मुख्यमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया।" राज्य में अगला चुनाव 2027 में होगा।

उन्होंने आगे कहा कि "मुख्यमंत्री धामी को कई विधायकों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ऐसे मामले इस बात को उजागर करते हैं कि पार्टी के नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बने रहेंगे। यह एक बहुत छोटा राज्य है, लेकिन राजनीति के लिहाज से यह सबसे बड़े राज्यों में से एक है। खनन सचिव संत के अनुसार, 2002 में राज्य के गठन के बाद से खनन राजस्व कभी भी 200 करोड़ रुपये से अधिक नहीं रहा। लेकिन धामी सरकार के कार्यकाल में, यह

पेपर लीकः

युवाओं के सपनों पर स्याही का धब्बा

उत्तराखण्ड में पिछले कुछ वर्षों में जितने पेपर लीक हुए, उतने शायद किसी छोटे राज्य में नहीं यूकेएसएसएससी, यूकेपीएससी पटवारी, पुलिस भर्ती, जेई, एई, और कई अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक ने राज्य की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 2022 में यूकेएसएसएससी ग्रेजुएट भर्ती पेपर लीक ने तो जैसे युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया। परीक्षा के बाद जब पता चला कि पेपर पहले ही बेच दिए गए थे, तो हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आये। राज्य की एसआईटी ने जांच शुरू की, सैकड़ों गिरफ्तारियाँ हुईं। कुछ आयोग के अधिकारी, और राजनीतिक रसूखदार के नाम भी सामने आए। लेकिन एक-एक कर लगभग सबको जमानत मिलती गई, जिससे युवाओं में भारी असंतोष व्याप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में हुआ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, रावत ने रविवार को कहा, "मैंने सदन में उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था, न कि सामान्य खनन का।" वहीं नवंबर 2022 रावत ने देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की धीमी गति की भी आलोचना की थी, जिसके कारण उन्होंने इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी।

भाजपा के कई नेता गाहे बगाहे त्रिवेन्द्र सिंह रावत का बचाव करते नजर आते हैं और उनके बचाव में भी रहते हैं। वहीं धामी सरकार कई ऐसे फैसले ले रही है जिनकी जनता आलोचना कर रही है और यह ज़रूरी है कि कुछ जायजा लिया जाए क्योंकि यह हमारी देवभूमि है। धामी सरकार ने रावत द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए कई फैसलों को पलट दिया था। उदाहरण के लिए, आलोचनाओं का सामना करते हुए, धामी सरकार ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त कर दिया था, जिसका उद्देश्य चार धाम हिंदू तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार करना था। रावत सरकार ने दिसंबर 2019 में यह कानून बनाया था और 15 जनवरी 2020 को इसे अधिसूचित किया था।

सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले भी राज्य के बेरोजगार युवकों की मांगों के पक्ष में बयान दे चुके हैं। यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक मामले ने राज्य की राजनीति और युवाओं को झकझोर कर रख दिया है। एक ओर प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एसआइटी से मामले की तहकीकात करवा रही है, तो दूसरी ओर बेरोजगार युवा पारदर्शिता और न्याय की गारंटी के लिए सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में अब हरिद्वार से भाजपा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगार युवाओं का समर्थन करते हुए कहा कि ''यदि युवाओं का विश्वास सीबीआई जांच से बहाल होता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, सरकार को इसकी संस्तुति कर देनी चाहिए।'' राजनीतिज्ञों के अनुसार माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी असहज व दबाव में दिखे। जिसकी वजह से वह आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच जाने और सीबीआई जांच की संतुति देने पर मजबूर हो गये। वहीं दूसरी ओर सीबीआई संतुति होने के बाद उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही आंदोलन स्थगित हुआ प्रदेश में राजनीति ओर गरमा गई और श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ढोल नगाड़ो के साथ मिठाई खिलाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और अभार जताया।

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, त्रिवेंद्र की सक्रियता से मुख्यमंत्री धामी और संगठन, दोनों सतर्क हैं। केंद्र के निर्देश पर दोनों के बीच टकराव से बचने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पार्टी जानती है कि पेपर लीक और युवाओं का गुस्सा अगले चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है।

आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

इस पूरी घटनाक्रम के बीच अब देखना यह होगा कि भाजपा हाई कमान टीएसआर को कैसे आंकती है, जबकि 2027 में राज्य में विधान सभा चुनाव होने हैं और वर्तमान धामी सरकार के कई निर्णय पर जनता अपना विरोध दर्ज करा चुकी है, उधर कांग्रेस भी हमलावर है ऐसे में भाजपा के लिये आगामी चुनाव में कई दिक्कते सामने आ सकती है।

बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़

जीवनरक्षक दवाएं बनी मौत का डोज

मनोज कुमार अग्रवाल
लेखक

हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार मिलावट और मुनाफाखोरी का तंत्र किस सीमा तक विकसित हो चुका है यह मध्यप्रदेश और राजस्थान में एक खांसी की दवा के सेवन से 18 बेगुनाह बच्चों की मौत से पता चलता है। यह स्थिति देश में दवाओं के कारोबार में भ्रष्ट सरकारी मशीनरी के संरक्षण में पनपे दवा सिंडिकेट का खुलासा करती है जो अपने मुनाफे और रिश्वतखोरी के लिए आमजन के जीवन से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। जांच के नाम पर लीपापोती की कवायद शुरू हो चुकी है। सरकारी मशीनरी अपनी खाल बचाने के लिए जांच का खेल खेल रही है जबकि इस सबके लिए भ्रष्टाचार ही जिम्मेदार है। सरकारी अस्पतालों के हाल किसी से छिपे नहीं हैं। वहां जो व्यवस्थाएं है और जिस तरह से दोयम दर्जे की दवा सप्लाई हो रहीं हैं वह किसी से छिपा नहीं है।

खांसी की दवा के नाम पर जहर पीने के बाद 18 बच्चों की मौत के बाद 'कोल्डरिफ' नामक सीरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस सीरप का प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डाक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डाक्टर और कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये कफ

सीरप तमिलनाडु की श्री सन फार्मास्यूटिकल्स फार्मा कंपनी से बनकर आए थे। मध्यप्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों ने भी इस कफ सीरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, 2022 में कफ सिरप पीने के बाद तीन देशों में 300 बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। इसके पहले मध्यप्रदेश ने नेक्स्ट्रो जीएस और कोल्ड्रिफ सीरप पर रोक लगाई थी। स्थितियों की गम्भीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार की ओर से भी दो वर्ष से कम के बच्चों को सीरप देने पर रोक लगा दी गई है । सीरप पीने के बाद हुई बच्चों की मृत्यु के बाद उनकी बायोप्सी रिपोर्ट में सीरप में डायएथिलीन ग्लायकॉल मिलने की पुष्टि हुई। जिससे बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। छिंदवाड़ा में तो 24 अगस्त को यह मामला आया जिसमें 20 दिनों में नौ बच्चों की सीरप पीने से मृत्यु हुई थी। इसके बाद भरतपुर में भी यह प्रकाश में आया कि यही सीरप पीने से वहां भी बच्चों की मृत्यु हुई। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. पवन नांदुलकर की मानें तो उनका कहना है कि ज्यादातर कार के इंजन में डाले जाने वाले कूलेंट, पेंट्स या ग्रीस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह कितना दुखद है कि जीवन रक्षा या उपचार के लिये दी जाने वाली दवा ही मौत का कारण बन गयी। जो दवा की संदिग्ध गुणवत्ता और निर्माता कंपनियों की आपराधिक लापरवाही को ही उजागर करती है। राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत की वजह का संबंध उस सिरप से बताया जा रहा है, जो खांसी ठीक करने के लिये दिया गया। ये हादसे इस बात को बयान करते हैं कि दवा की गुणवत्ता में चूक सामान्य उपचार को कितने जानलेवा जोखिम में बदल सकती है। बताया जाता है कि बच्चों को कथित रूप से मुख्यमंत्री की मुफ्त दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में एक जेनेरिक खांसी की सिरप दी गई थी। अब इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन यह त्रासदी भारत की फार्मास्यूटिकल निगरानी तंत्र की कोताही ही उजागर करती है। खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जो फार्मा हब के रूप में प्रमुख रूप से उल्लेखित है। महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की 655 फार्मास्यूटिकल इकाइयों में से केवल 122 ही मानकों पर खरी उतरी थी। इसका मतलब यह है कि अधिकांश फार्मा इकाइयां गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को प्रमाणित किए बिना काम कर रही हैं। ये जनस्वास्थ्य के प्रति कितनी गैरजिम्मेदार स्थिति है। जबकि हकीकत यह है कि फार्मास्यूटिकल इकाइयों को अपग्रेड करने की समयसीमा कई बार बढ़ाई गई है। यह नियामक तंत्र की कमजोरियों और छोटी फर्मों में सुरक्षित प्रक्रियाओं में निवेश करने की अनिच्छा को ही उजागर करती है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनके लिये कोई भी मुआवजा उनके बच्चों के प्राण नहीं लौटा सकता है। इस घटना के जिम्मेदार सरकारी और दवा निर्माता सभी की लापरवाही अक्षम्य है। इस आपराधिक लापरवाही करने वालों को कठोरतम दंड से दंडित किया जाना चाहिए । स्थिति यह है कि अतीत में भी ऐसी कई त्रासदियां हुई हैं, लेकिन हमारे तंत्र ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। हालांकि अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को परामर्श जारी किया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाइयां नहीं दी जाएं। वर्ष 2020 में भी एक ऐसी त्रासदी सामने आई थी, लेकिन कुछ दिन के शोर के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विडंबना देखिए कि मृत बच्चों के परिजन आज भी न्याय की प्रतीक्षा में आंसू बहा रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसी मौतों की जिम्मेदारी तय करने में लगातार देरी होती रहती है। ऐसे हादसों को या तो कमतर दर्शाया जाता है या फिर पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है पिछले साल भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था।

निस्संदेह, ऐसे गैर-जिम्मेदार तरीके से तैयार दवाइयों के चलते भारत की 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में हासिल प्रतिष्ठा को ही नुकसान पहुंचा है। हमारे नियामक तंत्र को और कितने बच्चों के मरने का इंतजार है।

भारत की फार्मा कंपनियों में निर्मित सिरप से गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का लिंक पाए जाने के बाद भारतीय दवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे। निस्संदेह, ऐसे गैर–जिम्मेदार तरीके से तैयार दवाइयों के चलते भारत की 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में हासिल प्रतिष्ठा को ही नुकसान पहुंचा है। हमारे नियामक तंत्र को और कितने बच्चों के मरने का इंतजार है। जरूरी है इससे पहले गुणवत्ता नियंत्रण सिर्फ कागज पर नहीं व्यवहार में लागू करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने दवाइयों के गुणवत्ता मानकों को तय के लिए सख्त तरीके जीएमपी अनुपालन हेतु समय–समय पर निरीक्षणों के लिये कदम उठाए हैं। लेकिन प्रवर्तन के स्तर पर अभी भी तमाम खामियां बरकरार हैं। विडंबना यह है कि राज्य नियामकों के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। साथ ही अकसर दंड के प्रावधान प्रभावी नहीं होते। यह एक कटु सत्य है कि भारत की फार्मा सफलता की कहानी केवल सस्ती जेनेरिक दवाइयों पर आधारित नहीं रह सकती। हमें इसे विश्वसनीय बनाने की जरूरत है। इसके लिए मजबूत ऑडिट, लापरवाही के लिए आपराधिक जिम्मेदारी तय हो और मामलों में पीड़ितों को तीव्र न्याय मिलना चाहिए। अन्यथा, ऐसी हर त्रासदी जन–विश्वास को कमजोर करती है, जो किसी भी दवा में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मध्य प्रदेश

और राजस्थान में कथित रूप से जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने छह राज्यों में दवा निर्माण इकाइयों की जांच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चल रही हैं, जहां से कुल 19 दवाओं जिनमें खांसी की दवाएं, एंटीबायोटिक्स और बुखार की दवाएं शामिल हैं के सैंपल लिए गए।

इस जांच का उद्देश्य दवा निर्माण प्रक्रिया में संभावित खामियों की पहचान करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाना है। तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित निर्माण इकाई से लिए गए कफ सिरप के सैंपलों की जांच में केमिकल की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने इस खांसी की दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया और बाजार से स्टॉक हटाने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही कंपनी के कांचीपुरम स्थित संयंत्र पर निरीक्षण कर उत्पादन भी रोका गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसकी बिक्री पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया। कफ सीरप पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ जिले में स्थित फार्मा कंपनियों पर कफ सिरप के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान 5 यूनिट्स का परमिशन खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का कारण 'कोल्ड्रिफ' सिरप बनी है।

अफ्रीकी देश गाम्बिया में जिस भारतीय कंपनी का कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हुई है, वह काफी लंबे समय से विवादों में चली आ रही है। हरियाणा के सोनीपत में स्थित मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड नाम की इस कंपनी को कई राज्यों में संदिग्ध मानकर कार्रवाई की जा चुकी है। मेडेन फार्मास्युटिकल्स उन भारतीय 39 दवा निर्माता कंपनियों में शामिल है, जिन्हें वियतनाम ने दवा नियंत्रक मानकों के उल्लंघन में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। गुजरात, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी यह दवा निर्माता कंपनी विवादित रह चुकी है। केरल, गुजरात और बिहार की राज्य सरकारें तो मेडेन फार्मास्युटिकल्स पर कार्रवाई कर चुकी हैं।

दोषी सिर्फ दवा निर्माता कंपनियां ही नहीं हैं, सरकारी मशीनरी में रिश्वत खा कर गैर मानक दवाओं के इस्तेमाल की छूट देने वाले अफसर ऐसी वारदातों के लिए सफेदपोश हत्यारे हैं। इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार मुआवजा देकर या जांच का नाटक कर अपनी जबावदेही से नहीं बच सकती है। कोई भी मुआवजा बच्चों का जीवन नहीं लौटा सकता है।

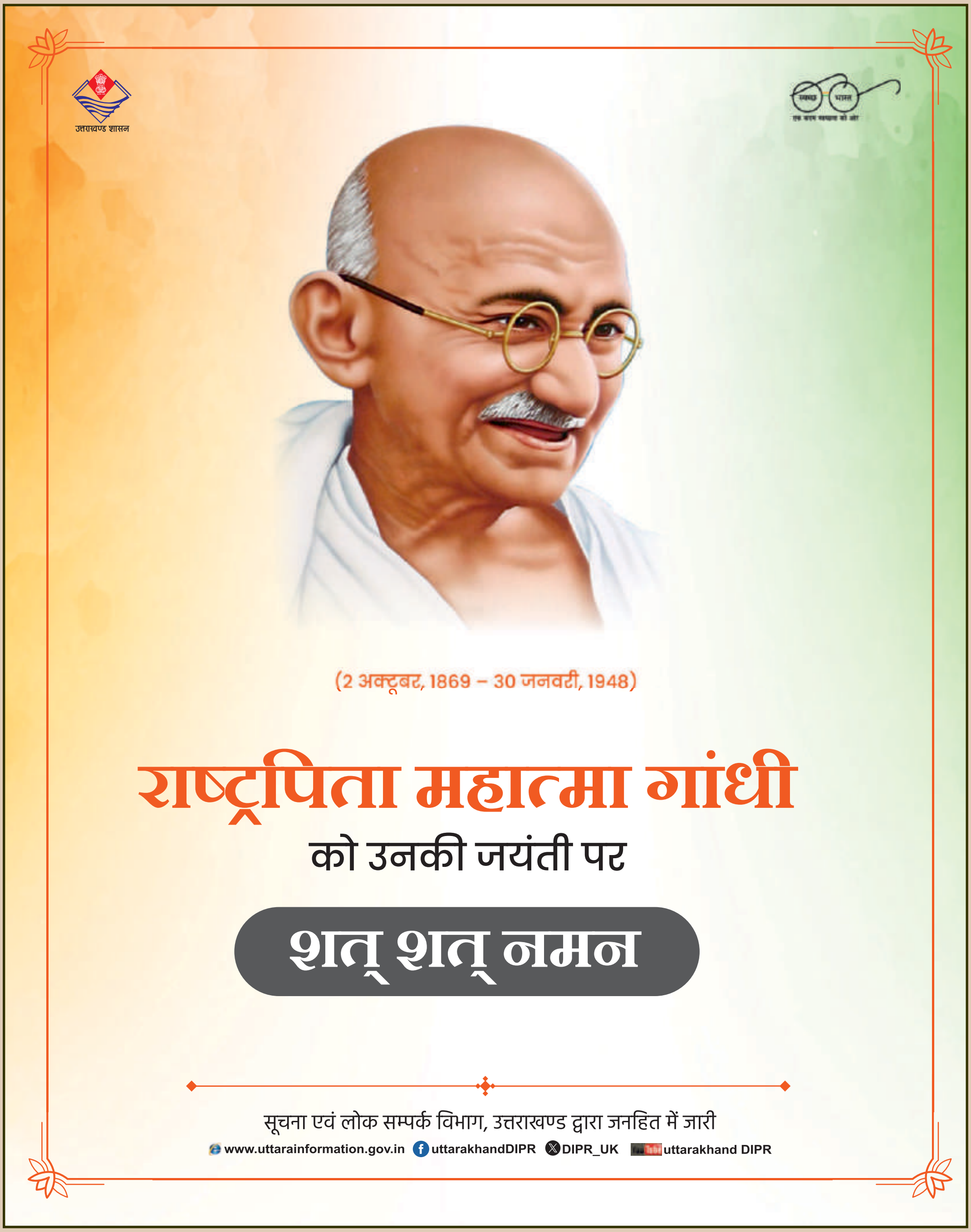

भारतीय राजनीति का बदलता चेहरा

विचारधारा से सत्ता तक

शहजाद अली
स्वतंत्र पत्रकार

जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तब राजनीति सेवा और राष्ट्र निर्माण का माध्यम मानी जाती थी। उस दौर के राजनेता सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए राजनीति करते थे। गांधीजी का राजनीति में आने का उद्देश्य जनसेवा, सत्य और नैतिकता को सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाना था।

नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद या डॉ. अंबेडकर जैसे नेता वैचारिक रूप से भिन्न होते हुए भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते थे। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भारतीय राजनीति का स्वरूप बहुत बदल चुका है। अब राजनीति सेवा से ज़्यादा सत्ता, प्रभाव और निजी लाभ का माध्यम बन गई है। विचारधाराएँ मौजूद हैं, मगर उनका पालन कम और उपयोग ज़्यादा होता है- विचारधारा से अधिक सत्ता ही लक्ष्य बन गई है।

राजनीतिः तब और अब

1947 के बाद का दौर वह था जब राजनेता आदर्शों के प्रतीक थे। राजनीति में प्रवेश करने का अर्थ था- राष्ट्र की सेवा करना। आज 21वीं सदी का दौर है, जहाँ राजनीति व्यवसाय, प्रतिष्ठा और प्रभाव का माध्यम बन चुकी है। नैतिकता, वैचारिकता और जनसेवा की भावना धीरे-धीरे कमजोर हुई है।

भारतीय राजनीति में विचारधाराओं की भूमिका

भारतीय राजनीति केवल सत्ता संघर्ष नहीं,

बल्कि विचारों का संघर्ष भर ही है। यहाँ हर दल किसी न किसी वैचारिक पथ पर चला- कभी धर्म के आधार पर, कभी वर्ग और जाति के आधार पर, तो कभी समाज और आर्थिक समानता के आधार पर।

भारत की प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं को पाँच वर्गों में बाँटा जा सकता है-

✦ हिन्दुत्व / राष्ट्रवाद (आरएसएस-बीजेपी)

✦ धर्मनिरपेक्ष उदारवाद (कांग्रेस)

✦ समाजवाद (सोशलीजम)

✦ बहुजनवाद (दलित-बहुजन पॉलीटिक्स)

✦ वामपंथ / मार्क्सवाद (लेफ्ट आइडीलॉजी)।

1. राष्ट्रवाद और हिन्दुत्वः भाजपा और आरएसएस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (1925) और बाद में भारतीय जनता पार्टी (1980) की विचारधारा हिन्दुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद पर आधारित है।

संघ का मानना है कि भारत मूलतः एक सांस्कृतिक राष्ट्र है जहाँ "हिन्दू" शब्द किसी धर्म नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा का प्रतीक है।

भाजपा इसी विचार को लोकतांत्रिक ढांचे में लागू करने का प्रयास करती है।

"एकात्म मानववाद" - व्यक्ति, समाज और प्रकृति का संतुलन

"सबका साथ, सबका विकास" - अन्त्योदय की आधुनिक अभिव्यक्ति

"राष्ट्र सर्वोपरि" - धर्म, जाति या वर्ग से ऊपर राष्ट्रहित

2. धर्मनिरपेक्ष उदारवादः कांग्रेस की विचारधारा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम में हैं। कांग्रेस की मूल विचारधारा लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर टिकी है। नेहरू ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाला राष्ट्र बनाने का सपना देखा, जबकि गांधीजी ने राजनीति में नैतिकता और अहिंसा का बीजारोपण किया।

✦ "विविधता में एकता" - यूनीटी इन डायवरसिटी

✦ धर्मनिरपेक्षता - राज्य और धर्म का पृथक्करण

✦ लोकतंत्र और समाजवाद - संविधान सर्वोपरि, जनता सर्वोच्च

✦ मिश्रित अर्थव्यवस्था - गरीबों के हित में विकास

3. समाजवादः समानता और जनकल्याण की राजनीति

समाजवाद का भारतीय संस्करण राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं से जुड़ा है। इनका मानना था कि जब तक समाज से आर्थिक और सामाजिक असमानता खत्म नहीं होगी, तब तक सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं।

समाजवादी विचारधारा का केंद्रबिंदु था "जिसके पास जो कमी है, राज्य उसे पूरा करे।" आज समाजवादी सोच सपा, राजद, जेडी(यू) जैसे दलों के रूप में जीवित है, यद्यपि व्यवहार में इसकी चमक कम हो गई है।

4. बहुजनवादः दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति

डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित यह राजनीति सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और बराबरी के सिद्धांत पर खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कुछ क्षेत्रीय दलों ने "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" के नारे से वंचित तबकों की आवाज़ को राजनीति में लाया।

बहुजनवाद का उद्देश्य था - "राजनीति पर वह कब्ज़ा, जो सदियों से वंचित रहा।"

5. मार्क्सवाद और वामपंथ

वामपंथी विचारधारा का केंद्र मार्क्सवाद है - जहाँ आर्थिक समानता और वर्गहीन समाज की स्थापना को लक्ष्य माना गया। भारत में यह विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) और सीपीआई(एम) जैसे दलों के माध्यम से प्रकट हुई। इन दलों ने श्रमिक वर्ग, किसानों और गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। हालाँकि, समय के साथ इस विचारधारा की पकड़ घटती गई, और आज "अर्बन नक्सल" जैसे शब्द उसके चरम रूपों की चर्चा में इस्तेमाल होते हैं।

आज की राजनीतिः विचारधारा या अवसरवाद?

जहाँ पहले विचारधारा दलों की पहचान हुआ करती थी, वहीं आज सत्ता और लाभ राजनीति का लक्ष्य बन चुके हैं। विचारधाराओं की जगह छवि, प्रचार, जाति समीकरण और मीडिया मैनेजमेंट ने ले ली है। जनसेवा के स्थान पर सत्ता-संरक्षण और दलीय निष्ठा से अधिक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढ़ी है। राजनीति अब विचार का क्षेत्र नहीं, बल्कि व्यवसाय का अखाड़ा बनती जा रही है।

राजनीति कैसी होनी चाहिए?

राजनीति तभी सार्थक होगी जब -

✦ वह सेवा का माध्यम बने, सत्ता का नहीं।

✦ विचारधारा और आचरण में सामंजस्य हो।

✦ दल और नेता जनता के प्रति जवाबदेह हों।

✦ लोकतंत्र का मूल उद्देश्य 'जनकल्याण' हो, न कि व्यक्तिगत लाभ।

भारत की राजनीति में विविध विचारधाराएँ हैं - हिन्दुत्व से लेकर समाजवाद और बहुजनवाद तक। लेकिन किसी भी विचारधारा की सफलता इसी में है कि वह मानवता, नैतिकता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। राजनीति विचार का माध्यम बने, न कि लाभ का बाज़ार - तभी भारत फिर वही राजनीति देखेगा, जो आज़ादी के दीवानों ने शुरू की थी।

वृद्धाश्रमः भारतीय पारिवारिक संरचना पर संकट

निराश्रितों, विकलांगों या पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय गृह समझ में आते हैं, लेकिन मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम एक अस्वाभाविक कदम प्रतीत होता है

देवेंद्र कुमार बुडाकोटी
लेखक

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के हर ज़िले में वृद्धाश्रम खोलने की हालिया घोषणा ने मुझे, एक समाजशास्त्री के रूप में, यह सोचने पर विवश किया कि क्या वास्तव में पहाड़ी समाज को वृद्धाश्रमों की आवश्यकता है? खासकर तब जब यहां परिवार का अर्थ केवल माता–पिता और बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विस्तृत रिश्तों की जड़ से जुड़ी व्यवस्था है।

यदि सरकार वाकई बुजुर्गों के हित में काम करना चाहती है, तो वह नागरिक समाज संगठनों को वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और उनके संचालन में सहायता कर सकती है। अधिकांश बुजुर्ग जो वृद्धाश्रमों में रहते हैं, वे आर्थिक और मानसिक रूप से सक्षम होते हैं और निजी संस्थानों द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार को वृद्धाश्रम नहीं, बल्कि निराश्रितों के लिए आश्रय गृह स्थापित करने चाहिए।

सार्वजनिक नीति अक्सर तब बनती है जब नागरिक समाज किसी मुद्दे को लंबे समय तक उठाता है और उसे जनचर्चा का विषय बनाता है। निराश्रितों, विकलांगों या पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय गृह समझ में आते हैं, लेकिन मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम एक अस्वाभाविक कदम प्रतीत होता है, खासकर भारतीय समाज की पारिवारिक परंपराओं को देखते हुए। भारतीय

> परिवार सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है। पड़ोसी भी रिश्तेदार बन जाते हैं। राखी भाई, राखी बहन, भाभी, भाई साहब जैसे संबोधन केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि भावनात्मक संबंध हैं। यहां तक कि दोस्तों के जीवनसाथी भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं।

पारिवारिक व्यवस्था गहराई से जुड़ी हुई है, और यही इसकी सामाजिक स्थिरता का आधार है। पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय परिवारों को ग्राम समुदाय, संयुक्त परिवार, विस्तारित परिवार और आधुनिक काल में विकसित हुए एकल (न्यूक्लियर) परिवार के रूप में वर्गीकृत किया है। किंतु भारत में, चाहे परिवार किसी भी प्रकार का हो, बुजुर्ग सदस्यों को अक्सर परिवार का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। एक उदाहरण देखेंकृजब किसी बेटी की विदाई विवाह के बाद होती है, तो केवल उसके माता–पिता ही नहीं, बल्कि पूरे गांव और मोहल्ले के लोग भावुक होकर रो पड़ते हैं। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भावनात्मक और पारिवारिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है।

भारत में रिश्तों की एक जटिल और मजबूत प्रणाली है, जहां बुजुर्ग माता–पिता की देखभाल आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना संतानें करती हैं। यदि कहीं किसी बुजुर्ग की उपेक्षा या दुर्व्यवहार होता है, तो वह खबर बनती है और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाता है। पश्चिमी समाजों में अधिकतर परिवार एकल होते हैं, और वहां वृद्धाश्रम जाना एक सामान्य बात है। वे शायद यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई बेटा अपने माता–पिता, पत्नी, बच्चों के साथ–साथ अपने चाचा (जिनके अपने सफल बेटे और बहुएं हैं) को भी साथ रखे। लेकिन भारत में यह सामान्य है।

यहां परिवार सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है। पड़ोसी भी रिश्तेदार बन जाते हैं। राखी भाई, राखी बहन, भाभी, भाई साहब जैसे संबोधन केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि भावनात्मक संबंध हैं। यहां तक कि दोस्तों के जीवनसाथी भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। विवाह का अधिकांश हिस्सा आज भी पारंपरिक रूप से तय होता है, जिससे रिश्तों की यह श्रृंखला बनी रहती है।

औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और शिक्षा या रोजगार के लिए पलायन ने एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि की है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में वृद्धाश्रम उभरने लगे हैं। लेकिन पारिवारिक मूल्यों की जड़ें अब भी गहरी हैं। कई परिवार भले ही भौगोलिक रूप से अलग रहते हों, लेकिन भावनात्मक रूप से वे जुड़े रहते हैं।

एक ऐसा समाज जो अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर सकता, धीरे–धीरे नैतिक और सामाजिक पतन की ओर बढ़ता है। यदि हम केवल संस्थागत सुविधा को अपनाते हुए भावनात्मक जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ लेंगे, तो हम एक दिशाहीन और विघटित समाज की ओर अग्रसर होंगे।

लेखक समाजशास्त्री हैं और चार दशकों से विकास क्षेत्र में कार्यरत हैं।

'आई लव मोहम्मद' विवाद

सांप्रदायिक हिंसा और ध्रुवीकरण का नया बहाना

मुस्लिम उत्सवों के प्रति ऐसी नफरत भरी प्रतिक्रिया से, जैसा हाल के समय में हो रहा है, दिलों में घृणा बढ़ती है, समुदायों का ध्रुवीकरण होता है और बंधुत्व के मूल्यों का अवमूल्यन होता है जो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है।

राम पुनियानी

(लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मनी अवार्ड से सम्मानित हैं)

सांप्रदायिक हिंसा भारतीय राजनीति का अभिशाप है। यह सौ वर्ष से अधिक पुरानी है। इसके अधिकांश अध्येताओं का मत है कि यह सामान्यतः योजना बनाकर की जाती है। इस हिंसा के बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के हालात बन जाते हैं। अध्येताओं का यह मत भी है कि "दंगों के नतीजे में होने वाले धार्मिक ध्रुवीकरण से धर्म की राजनीति करने वाले राजनैतिक दलों का लाभ होता है और कांग्रेस को नुकसान''। उनका मानना है कि इन दंगों के नतीजे में "बहुधर्मी प्रकृति वाले कांग्रेस जैसे दलों को चुनावों में नुकसान होता है, सांप्रदायिक दलों को लाभ होता है और उनकी शक्ति बढ़ती है''। इसी उद्देश्य से चुनावी लाभ के लिए हिंसा करने के नए–नए बहाने गढ़े जाते हैं।

बहानों की इस लंबी फेहरिस्त में आए दिन नए–नए मुद्दे जोड़ दिए जाते हैं। मस्जिद के सामने तेज संगीत बजाना, मंदिरों में गौमांस फेंकना और अफवाहें फैलाना नफरत बढ़ाने

बरेली में कुछ दिनों तक इंटरनेट बंद रहा और एक स्थानीय मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा खान को उनके घर में ही एक सप्ताह तक नजरबंद रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जांच-पड़ताल के मुसलमानों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कानपुर की घटना पर एक ज्ञापन सौंपे जाने का आव्हान किया।

की इस प्रवृत्ति के केन्द्र में रहते हैं। इसमें मुस्लिम राजाओं का दानवीकरण, उनके द्वारा मंदिर तोड़े जाने, तलवार की नोंक पर इस्लाम फैलाने, उनके अधिक बच्चे पैदा करने के कारण हिंदुओं के देश में अल्पमत में हो जाने जैसे मुद्दे नफरत फैलाने की इस प्रक्रिया में जोड़ दिए गए हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इसमें गाय, गौमांस सेवन, लव जिहाद और कई अन्य जिहाद जिनमें कोरोना जिहाद, भूमि जिहाद और हाल ही में जोड़ा गया पेपर लीक जिहाद मुख्य हैं, जुड़ते देखे हैं।

इस सबके साथ इन दिनों हम 'आई लव मोहम्मद' के सीधे–सादे नारे को लेकर हिंसा भड़काने के नजारे देख रहे हैं। इसकी शुरूआत कानपुर से हुई जब मिलादुन्नबी के दिन पैगम्बर मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर निकाले गए जुलूस में शामिल 'आई लव मोहम्मद' बैनर पर कुछ लोगों द्वारा इस आधार पर आपत्ति की गई कि इस धार्मिक उत्सव में यह नई परंपरा जोड़ी जा रही है। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों में से कुछ ने इस तर्क को सही मानते हुए ऐसे बैनर पकड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एक शांतिपूर्ण जुलूस में लोगों द्वारा अपने पैगम्बर के प्रति सम्मान दर्शाना पूरी तरह वाजिब था और किसी भी कायदे–कानून का उल्लंघन नहीं था। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसा फैल गई।

कानपुर की घटना पहली थी और यह उत्तर प्रदेश के बरेली, बाराबंकी और मऊ जिलों में और उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और कई अन्य स्थानों पर दुहराई गई। इसकी प्रतिक्रिया में पोस्टर फाड़े गए, उसके बाद हिंसा हुई और माहौल विषाक्त हो गया। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राईट्स (एपीसीआर) द्वार एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार अब तक आई लव मोहम्मद वाले मुद्दे पर 1324 लोगों के खिलाफ 21 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली में कुछ दिनों तक इंटरनेट बंद रहा और एक स्थानीय मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा खान को उनके घर में ही एक सप्ताह तक नजरबंद रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जांच–पड़ताल के मुसलमानों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कानपुर की घटना पर एक ज्ञापन सौंपे जाने का आव्हान किया। पर वे स्वयं इसके लिए नहीं पहुंचे। नतीजे में अफरातफरी हुई और बड़े पैमाने पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। इस घटनाक्रम से मुसलमानों के प्रति नफरत भी सामने आ गई है। बड़े नेताओं ने इशारों–इशारों में बात की और छुटभैये नफरत और हिंसा फैलाने में जुट गए। मोदी लगातार, बार–बार ऐसा करते रहे हैं, खासतौर पर चुनाव के आसपास। इस बार उनका अभियान घुसपैठियों के मुद्दे पर केन्द्रित है। यह सब मुसलमानों, खासकर बिहार और असम के मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफदेह बन गया है। एसआईआर के कदम को उचित ठहराने का एक आधार यह भी था और इसे बिहार के बाद, जहां 47 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है, सारे देश में किए जाने की योजना है।

इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंसक घटनाएं हुई और वहां के मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ ने ऐसे वक्तव्य दिए जो एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा कि वे 'गजवा–ए–हिंद' का नारा बुलंद करने वालों के नर्क के टिकिट कटवा देंगे। यह 'गजवा–ए–हिंद' की बात कहां से आ गई? भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग 'आई लव मोहम्मद' का नारा लगा रहे हैं, ना कि गजवा... गजवा का नारा, जो तालिबानी किस्म के लोगों द्वारा लगाया जाता है। मगर हिंदू दक्षिणपंथी पूरे मुस्लिम समुदाय को इसके लिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वैसे भी गजवा ए हिंद का कुरान में कोई जिक्र नहीं है। एक हदीस, जिसके असली होने में संदेह है, में इस शब्द का जिक्र है मगर उसमें भी हिंद से आशय बसरा से है भारत से नहीं। पाकिस्तान में कई कट्टरपंथी यह दावा करते हैं कि भारत के खिलाफ हर युद्ध गजवा है।

योगी ने यह भी कहा कि 'आई लव मोहम्मद' वाले पोस्टर अराजकता के हालात बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं से हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सावधान रहने को कहा। (इंडियन एक्सप्रेस, मुंबई संस्करण, 29 सितंबर पृष्ठ 6)। यह भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत पैदा करने का निकृष्टतम उदाहरण है। इस नारे से अराजकता कैसे उत्पन्न हो सकती है? यह नारा किस तरह से राष्ट्रविरोधी है, यह समझ के परे है। उनके वक्तव्य लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हैं, जिनके अंतर्गत हमें अपनी भावनाएं शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करने का अधिकार है।

'आई लव मोहम्मद' का पूरा मामला मुसलमानों को आतंकित करने और उन्हें हाशिए पर पटकने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अपने पैगम्बर के प्रति स्नेह की इस प्रकार की अभिव्यक्ति पूरी तरह अभिव्यक्ति की आजादी के लोकतांत्रिक अधिकार की सीमाओं के अंदर है। जैसे पाकिस्तान में कुछ तालिबानी तत्व दावा करते हैं कि भारत के साथ हर भिड़ंत गजवा है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री भी मसलों को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। क्रिकेट में पाकिस्तान पर विजय के बाद उन्होंने कहा कि यह आपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है। ऐसे हालातों में मुस्लिम समुदाय को किस तरह की प्रतिक्रिया करनी चाहिए? इस तरह के शांतिपूर्ण जुलूस निकालना एकदम उचित है। इसके विपरीत हैं रामनवमी के जुलूस जिनमें डीजे पर तेज संगीत बजता है और मस्जिदों पर भगवा झंडा लहरा दिया जाता है! हमारे कई हिंदू उत्सवों का सशस्त्रीकरण किया जा रहा है! इरफान इंजीनियर और नेहा दाभाड़े ने अपनी पुस्तक 'वेपनाईजेशन ऑफ हिंदू फेस्टिविल्स' में अपनी मैदानी जांच–पड़ताल के माध्यम से बताया है कि विशेषकर रामनवमी के जुलूस के जरिए मस्जिदों और मुस्लिम बहुल इलाकों के आसपास अफरातफरी का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि मुस्लिम उत्सवों का दानवीकरण किया जा रहा है। मिलादुन्नबी कां 'आई लव मोहम्मद' के माध्यम से दानवीकरण किया जाना इसका एक दुःखद उदाहरण है।

मुस्लिम उत्सवों के प्रति ऐसी नफरत भरी प्रतिक्रिया से, जैसा हाल के समय में हो रहा है, दिलों में घृणा बढ़ती है, समुदायों का ध्रुवीकरण होता है और बंधुत्व के मूल्यों का अवमूल्यन होता है जो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, वे संवैधानिक नैतिकता के विपरीत हैं। मुस्लिम समुदाय को हिंदू साम्प्रदायिक तत्वों को हिंसा प्रारंभ करने का कोई बहाना उपलब्ध नहीं कराना चाहिए जिसके जरिए वे उन पर आक्रमण कर सकें या उनका और अधिक दानवीकरण कर सकें।

मुस्लिम छात्रा ने देश में एकता और भाईचारा के लिए उठाया बेहतरीन कदम

✦ करवा चौथ पर हिंदू महिलाओं को दिए उपहार।
✦ सबको आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए : डॉ शगुफ्ता
✦ मेरा हौसला मेरे गुरुजनों के मिल रहे आशीर्वाद, मेरे समाज सेवा के संकल्प को और मजबूत कर रहा

रेडियोलोजी की एक छात्रा डॉ शगुफ्ता जहां जहां ने खुद मुसलमान होते हुए करवा चौथ के अवसर पर अपनी हिंदू बहनों को उपहार दिए जिसमें साड़ी चूड़ी मेहंदी बिंदिया इत्यादि श्रृंगार का सामान भी शामिल है।

इस अवसर पर डॉ. शगुफ्ता जहां ने बताया कि आज समाज में कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर कर भेदभाव पैदा कर रहे हैं जबकि जिस समाज में हम रह रहे हैं यहां सबको आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे के सहयोग के बिना हम एक सबवे समाज नहीं बना सकते उन्होंने बताया कि इस काम में मुझको मेरे कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर जीडीएस वार्नये साहब टीचिंग स्टाफ जिसमें डॉ आशीष, डॉ मीनू मरवाह, मैडम स्वती बंसल, मैडम मेहविश मलिक, डॉ दीपांजीत, दो निहारिका थपलियाल, डॉ बिमल, शुभम सिंघल असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी विभाग और मेरे फादर इरफान अहमद साहब के अतिरिक्त प्रेम बहादुर राय और डॉ. उस्मानी का मार्गदर्शन प्राप्त रहा है।

डॉक्टर शगुफ्ता जहां ने बताया कि कुछ महिलाओं ने मेरा उपहार यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि हमें मुस्लिम के हाथ से नहीं लेना है लेकिन इस सब के बावजूद मेरा हौसला मेरे गुरुजनों के मिल रहे आशीर्वाद मेरे समाज सेवा के संकल्प को और मजबूत कर रहा है।

उत्तरप्रदेश में मायावती की नई चुनौती

डॉ. सुधाकर आशावादी
लेखक

कब कोई राजनीतिक विचार किसी दल को सत्ता का स्वाद चखा दे, अब कब कोई विचार सत्ता से अलग कर दे, यह कोई नहीं जानता। इसी कारण देश की राजनीति में विघटनकारी जातीय गठबंधन की राजनीति कारगर सिद्ध होगी या सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की राजनीति , यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, किन्तु लंबे समय तक हाशिये पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ लोकतंत्र के चुनावी मैदान में उतर आई है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े,दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर समाज को बांटने में जुटी समाजवादी पार्टी के लिए यह खतरे की घंटी सिद्ध हो सकता है।

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की स्मृति में लखनऊ में आयोजित सुश्री मायावती की रैली में बसपा समर्थकों ने जिस प्रकार से बसपा की जड़ों को मजबूत करने का जज्बा दिखाया है, उससे लगता है कि गहन मंथन के बाद बसपा नए प्रारूप में उभर कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दमखम दिखाएगी तथा 2027 में सत्ता में आने का दिवास्वप्न देखने वाली समाजवादी पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा की बरसों तक बड़ी उपस्थिति रही है। एक दौर था कि जब प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा हाशिये पर चली गई थी। अपने जातीय समीकरणों के कारण समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता का खेल खेलते रहे। सुश्री मायावती ने 18 सितंबर साल 2003 को पहली बार पार्टी की कमान संभाली थी। इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने जमकर मेहनत की और चार साल में ही पार्टी के लिए एक ऐसा स्वर्णिम अवसर लाने में सफल हुईं जो इतिहास में दर्ज हो गया। वह साल था 2007 जब उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। सुश्री मायावती वर्ष 2007 में चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थीं, यह उनके राजनीतिक जीवन का स्वर्णिम काल था। साल 2003 से लेकर 2024 तक मायावती सात बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी हैं। वर्ष 2003 से लेकर साल 2024 तक बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। वर्तमान में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पूरी दृढ़ता के साथ गतिशील है तथा विगत लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को अति आत्मिश्वास के कारण अनेक संसदीय क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा तथा समाजवादी पार्टी की कृपा से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कदम रखने की जगह मिली, उसका कारण बसपा की तत्कालीन चुनावों में सक्रिय भागीदारी न होना भी रहा है। लखनऊ में सुश्री मायावती की हुंकार ने यह जता दिया है, कि आज भी बहुजन समाज के शुभचिंतकों के हृदय में बसपा धड़कती है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर विघटन का खेल खेलने वाली समाजवादी पार्टी के दिन लद गए हैं।

समझना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास की नीतियां ही राजनीतिक दलों को सत्ता की संजीवनी प्रदान कर सकती हैं। जातीय विघटनकारी षड्यंत्रों को जनता समझ चुकी है। वह किसी भी राजनीतिक दल के विघटनकारी मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। बसपा इस बार अपनी नई सोच के साथ यदि चुनाव मैदान में अपना दमखम दिखाती है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर सकती है। ऐसा समझा जाना चाहिए।

गुरू फॉरेन्सिक एण्ड डिटेक्टिव एजेंसी

सभी देश व प्रदेश वासियों को

दीपावली

की हार्दिक शुभकामनाएं

1. घरेलू निगरानी
2. निजी अत्याचार की जांच
3. बच्चों की सुरक्षा व उनका उत्पीड़न
4 विवाह सम्बंधित जांच करवाना
5. पति/पत्नी में मतभेद की जांच करवाना
6. फिंगर प्रिन्ट निरीक्षण
7. हस्तलेख व हस्ताक्षर जांच
8. विवादास्पद प्रलेख जांच में दक्ष

हेड ऑफिस :– गली न0–5, मोनाल एनक्लेव, बंजारावाला, देहरादून।
ब्रांच :– नथनपुर, रिंग रोड, जोगीवाला, देहरादून।
फोन न0. 0135–2532999, 9675331055, 9568728805
E-mail:- guruforensic2015detective@gmail.com

कुमार स्वीट शॉप

की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को

दीपावली

व भैयादूज

की हार्दिक शुभकामनाएं

पताः एमडीडीए कॉम्प्लेक्स, नियर घंटाघर, देहरादून।

लालू परिवार की मुश्किलें

विशेष संवाददाता

> लालू पहले ही चारा घोटाले में, स्वास्थ्य के आधार पर, जमानत पर हैं। कई साल जेल की सजा भी काट चुके हैं।

बिहार चुनाव तपने लगा था, उसी दौरान सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अब चुनाव के दौरान ही 27 अक्तूबर से रोजाना अदालत सुनवाई करेगी, साक्ष्य पेश किए जाएंगे, बहस होगी और अंतिम चरण के मतदान 11 नवंबर से एक दिन पहले ही अदालत अपना अंतिम फैसला सुना सकती है। अर्थात लालू यादव और परिजनों को जेल भेजा जाएगा अथवा आरोप–मुक्त किया जाएगा।

लालू पहले ही चारा घोटाले में, स्वास्थ्य के आधार पर, जमानत पर हैं। कई साल जेल की सजा भी काट चुके हैं। यह केस लालू यादव के रेलमंत्री कार्यकाल का है, जब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी। लालू 2004–09 के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री थे। लालू के उस दौर में जमीन के

आरोप किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, बल्कि एक विशेष जज की अदालत में तय किए गए हैं, लिहाजा यह राजनीति करार नहीं दी जा सकती। अलबत्ता लालू परिवार इस अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती जरूर दे सकता है।

बदले नौकरियां दी गईं और भूमि के सस्ते हस्तांतरण के बदले आईआरसीटीसी होटल के घोटाले सामने आए।

विशेष जज विशाल गोगने ने लालू यादव के आपराधिक साजिश का मुख्य सूत्रधार होने की आशंका जताई है। आपराधिक साजिश के अलावा, धोखाधड़ी, सार्वजनिक पद के दुरुपयोग और जनसेवक द्वारा आपराधिक दुराचरण की धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने 244 पन्नों के फैसले में कहा है कि तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सुजाता होटल, प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी का होटल, के निदेशक विजय और विनय कोचर आदि के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। रांची और पुरी के बीएनआर होटलों की उप–लीज के अनुबंधों में अनुचित लाभ दिए गए। बदले में कोचर बंधुओं ने पटना की कीमती जमीन लालू के करीबी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी को बेची। वह कंपनी लालू परिवार के नियंत्रण में आ गई।

कंपनी के शेयर तेजस्वी और राबड़ी देवी के नाम कर दिए गए। जमीन हस्तांतरण भी मामूली कीमत पर उनके नाम हो गया। जिस संपत्ति का बाजार–मूल्य 94 करोड़ रुपए था और सर्किल रेट ही 32 करोड़ रुपए से अधिक था, वह 65 लाख रुपए में ही तेजस्वी और राबड़ी देवी के नाम कर दी गई। तब तेजस्वी नाबालिग थे, लेकिन करोड़ों रुपए की कंपनी और संपत्ति के मालिक थे। अदालत में वे कह रहे थे कि वे निर्दोष हैं। तो करोड़ों रुपए का हस्तांतरण उनके नाम कैसे हो गया? देश में किसी अन्य परिवार के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अदालत का गंभीर संदेह है कि तत्कालीन रेलमंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को भी प्रभावित किया। तेजस्वी यादव इस मामले को 'सियासी साजिश' करार दे रहे हैं और लगातार लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। भारत सरकार में रेल मंत्री लालू यादव थे, घोटाला परिवार में रचा गया, तो 'सियासी साजिश' कौन करेगा? यूपीए सरकार मई, 2014 तक रही। दरअसल यह घोटाला चक्रव्यूह की तरह है। आखिरी लाभार्थी लालू परिवार है। चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप और अंततरू कटघरे में जाने की नौबत राजद और 'इंडिया' गठबंधन के लिए करारा धक्का साबित हो सकता है।

भाजपा–एनडीए लालू परिवार के खिलाफ धुआंधार प्रचार करेंगे और इस घोटाले को 'जंगल–राज' तथा 'चारा घोटाले' की अगली कड़ी कहेंगे। आरोप किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, बल्कि एक विशेष जज की अदालत में तय किए गए हैं, लिहाजा यह राजनीति करार नहीं दी जा सकती। अलबत्ता लालू परिवार इस अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती जरूर दे सकता है। 'जमीन के बदले नौकरी' घोटाले के किरदार लालू की बेटियां–मीसा भारती, हेमा यादव–भी हैं। दरअसल जांच एजेंसियों को लालू परिवार के आर्थिक संसाधनों की सम्यक जांच करनी चाहिए। राबड़ी देवी और बच्चों ने न तो अच्छी नौकरी की और न ही उद्योग स्थापित किए, लेकिन उनके पास फॉर्म हाउस, घर, संपत्तियां कहां से आईं? कमोबेश देश को इस भ्रष्ट चक्रव्यूह की जानकारी मिलनी चाहिए।

सबसे संवेदनशील मामला तो तेजस्वी के लिए है। यदि अदालत ने उन्हें दो साल या अधिक की सजा सुना दी, तो उनका राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह चुनाव लड़ने या किसी सरकारी पद पर रहने के योग्य ही नहीं रहेंगे। लालू को चारा घोटाले में इतनी सजाएं सुनाई गई हैं कि वह चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं रहे हैं।

हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव के ऐन मौके पर लालू परिवार की छवि धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। किंतु सत्ता पक्ष की ओर से यह प्रचार किया जा रहा है कि इस तरह के मामलों की सुनवाई काफी समय से चल रही है, इसलिए विपक्ष के आरोप में दम नहीं है। उसका मानना है कि जानबूझ कर ऐसा नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके लिए लालू परिवार स्वयं जिम्मेवार है जिसने भ्रष्टाचार को अनके बार अंजाम दिया।

चीफ जस्टिस पर चला जूता अब सनातनी होकर पूजनीय हो चुका है, एक दिन इसका भी मंदिर बनेगा!

विष्णु नागर
लेखक

> **"सच्चा सनातनी है तो तनातनी पैदा करके दिखा। जल्दी से जल्दी अपना कोई दुश्मन ढूंढ। मुसलमान न मिले तो दलित का सिर आखिर किसलिए है? वह जितने भी बड़े पद पर हो, दलित है! एक जूता निशाने पर न लगे तो दूसरा मार! सनातन युक्त होकर जूता-मुक्त हो!"**

ये पैरों की रक्षा के लिए जूते नहीं पहनते, उन्हें किसी के सिर पर तान कर मारने के लिए पहनते हैं। जब तक इनके जूते इनके पैरों में रहते हैं, इन्हें काटते रहते हैं। काट-काट कर इन्हें याद दिलाते रहते हैं कि हे मूरख, तू भूल गया कि तूने ये जूते किसलिए खरीदे थे? इससे तुझे उस हिंदुत्व की रक्षा करना था- जिसने अभी-अभी सनातन की खाल ओढ़ रखी है। गधे, तूने इन्हें सनातन-विरोधियों के सिर पर मारने के लिए खरीदा था मगर तू इन्हें पहनने के मोह में पड़ गया। भौतिकता के जंजाल में फंस गया है। जूते का युगानुकूल सनातनी उपयोग करना भूल गया है। इन्हें खरीदने में लगे चंद रुपयों के मोहपाश में बंध गया है।

तू इसी तरह इन्हें पहनता चला गया तो तुझे इन जूतों से और इन जूतों को तुझसे प्यार हो जाएगा। फिर हिंदुत्व उर्फ सनातन, वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। आगे अपनी विजय पताका फहरा नहीं पाएगा। फिर तुझमें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा, जिनके लिए जूता केवल पैरों

सनातनियों को यह अमूल्य उपहार दे दिया। जज साहब भूल गए कि वापस करने पर जूते की यह जोड़ी बेहद कीमती और वंदनीय हो जाएगी। खासकर वह वाला जूता जो फेंका गया, वह ऐतिहासिक महत्व हासिल कर लेगा।

में पहनने की चीज है? इसलिए तू इन्हें किसी के सिर पर तान कर मार। सच्चा सनातनी है तो तनातनी पैदा करके दिखा। जल्दी से जल्दी अपना कोई दुश्मन ढूंढ। मुसलमान न मिले तो दलित का सिर आखिर किसलिए है? वह जितने भी बड़े पद पर हो, दलित है! एक जूता निशाने पर न लगे तो दूसरा मार! सनातन युक्त होकर जूता-मुक्त हो!

यह 'सनातन' की सनातन पुकार ही थी, जो अब वकालत का अधिकार खो चुके वकील साहब ने सुनी और जूता चला दिया! यह उन्हीं काटने वाले जूते से पैदा हुआ दर्द था, यह वही 'ईश्वरीय आदेश' था, जिसका पालन करते हुए उस वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका। यह जूतों की और उस वकील की असफलता नहीं कि निशाना ठीक नहीं लगा, बीच में अटक कर भटक गया। जूतों की कामयाबी इसमें है कि आजाद भारत के इतिहास में ये कोर्ट रूम में पहली बार चले। हिंदुत्व उर्फ सनातन के 11 साल के इतिहास में जूता फेंककर वकील फेमस हो गया और उससे अधिक उसका जूता प्रसिद्ध हो गया!

मोदी युगीन हर सनातनी की सबसे बड़ी आकांक्षा नाथूराम गोडसे बनने की है लेकिन इनकी मुश्किल यह है कि इन गोडसों को गांधी नहीं मिल रहे। एक गोडसे को मुख्य न्यायाधीश मिले तो उन पर जूता फेंक दिया। अब सनातनियों-तनातनियों के ये जूते एक-डेढ़ हजार रुपए के नहीं रहे, अब ये ग्यारह लाख के हैं। गवई साहब ने उस वकील के जूते वापस करवाकर अनजाने में ही सनातनियों पर बड़ा उपकार कर दिया। सनातनियों को यह अमूल्य उपहार दे दिया। जज साहब भूल गए कि वापस करने पर जूते की यह जोड़ी बेहद कीमती और वंदनीय हो जाएगी। खासकर वह वाला जूता जो फेंका गया, वह ऐतिहासिक महत्व हासिल कर लेगा। हिंदुत्व के म्यूज़ियम की वह शोभा बढ़ाने लगेगा!

भविष्य में किसी सनातनी के जूते अपने उद्देश्य में सफल भी रहे तो वे इस जूते के 'गौरवमयी' स्थान को हासिल नहीं कर पाएंगे। कोई और वकील अब गोडसे की जगह नहीं ले पाएगा! यह जूता अब सनातनी होकर पूजनीय हो चुका है। एक दिन इसका भी मंदिर बनेगा और राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले इस मंदिर का भी उद्‌घाटन सहर्ष करेंगे और हम ताली-थाली बजाएंगे!

2014 के बाद उभरे सनातनियों की यह हार्दिक इच्छा रहती है कि वे जीवन में कम से कम एक ऐसा काम अवश्य करें, जिसके बारे में कहा जा सके कि यह आजादी के बाद पहली बार हुआ है। जैसे किसी प्रधानमंत्री ने मई 2014 से पहले हर वाक्य में झूठ नहीं पिरोया था, किसी ने इससे पहले नाली की गैस से चाय बनाने के वैज्ञानिक प्रयास की प्रशंसा भी नहीं की थी, तब एक सनातनी प्रधानमंत्री पैदा हुआ और उसने यह कर दिखाया।

प्रधानमंत्री के ही नक्शे कदम पर चलते हुए इस सनातनी वकील ने जज पर जूता फेंकने का 'ईश्वर प्रदत्त' कार्य संपन्न किया। हिंदुत्व के अंतरिक्ष का यूरी गगारिन इतनी ही दूर जा सकता था। वैसे यूरी गगारिन बनने के अन्य प्रार्थी तो इससे भी आगे जाने की इच्छा रखते थे मगर पिछड़ गए। एक सनातनी युवा जज साहब का सिर दीवार पर जोर से मारकर फोड़ना चाहता था, एक और की इच्छा इनके चेहरे पर थूकने की थी। ये धरी की धरी रह गईं मगर जब तक सुप्रीम कोर्ट है और जब तक सौ प्रतिशत जज इनके अपने नहीं हो जाते, तब तक गोडसे बनने की कतार में खड़े होने वाले हतोत्साहित नहीं होंगे!

संविधान निर्माण में मुस्लिम दूरदर्शी समावेशी भारत के वास्तुकार

इंशा वारसी
जामिया मिलिया इस्लामिया

भारतीय संविधान का निर्माण केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह विविध समुदायों के बीच एक नैतिक अनुबंध था, जो उपनिवेशवाद की साझा पीड़ा और एक संप्रभु, समावेशी राष्ट्र के साझा स्वप्न से जुड़ा था। ऐसे समय में जब उपमहाद्वीप विभाजन और एकता के चौराहे पर खड़ा था, कई मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिक अलगाव के बजाय संवैधानिक लोकतंत्र का मार्ग चुना। संविधान सभा में बैठे इन दूरदर्शी लोगों ने धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समान अधिकारों को प्रतिष्ठित करने वाले एक कानूनी ढाँचे को आकार देने में मदद की। निष्क्रिय भागीदार होने से कहीं आगे, वे एक आधुनिक, बहुलतावादी भारत के सक्रिय निर्माता थे। उनका योगदान हमें याद दिलाता है कि भारत की अवधारणा कभी किसी एक धर्म या विचारधारा से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और एकता के लिए प्रतिबद्ध विचारों के एक गठबंधन से बनी थी।

इन दूरदर्शी लोगों में सबसे प्रमुख थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो एक विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। संविधान सभा में उनकी उपस्थिति प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण दोनों थी। एक कट्टर मुसलमान और कट्टर राष्ट्रवादी, आज़ाद ने लंबे समय से द्वि–राष्ट्र सिद्धांत को खारिज किया था। अपने भाषणों में, उन्होंने दोहराया कि भारत का भाग्य धार्मिक अलगाव पर नहीं, बल्कि साझा इतिहास, पारस्परिक सम्मान और एक साझा भविष्य पर आधारित हो सकता है। आज़ाद की बौद्धिक गंभीरता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता ने संविधान के कई प्रमुख प्रावधानों को प्रभावित किया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की

आज़ादी से पहले और बाद के वर्षों में, जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठनों और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे व्यक्तियों (हालांकि संविधान सभा में नहीं) ने भारत की एकता और संवैधानिक मूल्यों का पुरज़ोर समर्थन किया।

स्थापना और प्रशासन के अधिकारों की रक्षा करने वाले अनुच्छेद 30 का पुरजोर समर्थन किया। ये केवल संवैधानिक धाराओं से कहीं अधिक, नैतिक आश्वासन थे, खासकर उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने विभाजन के बाद भारत में रहने का विकल्प चुना था।

आज़ाद ने भारत की शिक्षा नीति को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा मंत्री के रूप में, उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की नींव रखी और सभी जातियों और समुदायों में वैज्ञानिक सोच और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके लिए, किसी राष्ट्र की प्रगति केवल संवैधानिक आदर्शों पर नहीं, बल्कि प्रबुद्ध नागरिकों पर निर्भर करती है। उन्होंने एक बार कहा था, 'दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। संविधान सभा में एक और महत्वपूर्ण मुस्लिम हस्ती बेगम ऐज़ाज़ रसूल थीं, जो इस ऐतिहासिक संस्था का हिस्सा बनने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। उनकी उपस्थिति ने ही रूढ़िवादिता को चुनौती दी और एक गहरे पितृसत्तात्मक समाज में मौजूद बाधाओं को तोड़ा। बेगम रसूल लैंगिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की प्रबल समर्थक थीं। उनकी आवाज़ ने एक एकीकृत चुनाव प्रणाली बनाने के संकल्प को मज़बूत किया, जो आज भी भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ बनी हुई है।

असम के पूर्व प्रधानमंत्री सैयद मोहम्मद सादुल्लाह एक अन्य प्रमुख व्यक्ति थे जिनकी अंतर्दृष्टि ने संघीय और अल्पसंख्यक हितों के बीच संतुलन बनाने में मदद की। नागरिकता और अल्पसंख्यक सुरक्षा उपायों पर बहस में उनके हस्तक्षेप ने भारत के बहुलवादी स्वरूप की एक परिपक्व समझ को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने कानूनी समानता और सामाजिक समरसता पर ज़ोर दिया, विशेषाधिकारों की नहीं, बल्कि ऐसे संरक्षणों की वकालत की जो हर भारतीय को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, फलने–फूलने का अवसर प्रदान करें।

ये मुस्लिम नेता अलग–थलग आवाज़ें नहीं थीं। वे मुस्लिम देशभक्ति के उस व्यापक परिवेश का हिस्सा थे जो इस विचार को खारिज करता था कि धर्म राष्ट्रीय निष्ठा का निर्धारण करे। आज़ादी से पहले और बाद के वर्षों में, जमीयत उलेमा–ए–हिंद जैसे संगठनों और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे व्यक्तियों (हालांकि संविधान सभा में नहीं) ने भारत की एकता और संवैधानिक मूल्यों का पुरज़ोर समर्थन किया। उनकी सामूहिक उपस्थिति सांप्रदायिक दुष्प्रचार का खंडन और भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में विश्वास की पुनः पुष्टि थी। भारतीय संविधान के निर्माण पर विचार करते हुए, हमें उन मुस्लिम नेताओं को अवश्य याद करना चाहिए जो इसके निर्माण में अग्रणी भूमिका में रहे, किसी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के दूरदर्शी के रूप में। उनकी विरासत केवल संविधान के पन्नों में ही नहीं, बल्कि उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं में भी समाहित है जिनका हम आज आनंद लेते हैं। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि आधुनिक भारत की नींव सभी धर्मों के लोगों के हाथों रखी गई थी। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह उन पुरुषों और महिलाओं के साहस, दूरदर्शिता और देशभक्ति का प्रमाण है जिन्होंने विभाजन के बजाय एकता को चुना। और उस पवित्र सभा में, मुस्लिम आवाज़ हाशिये से नहीं, बल्कि भारत के हृदय से गूंजी।

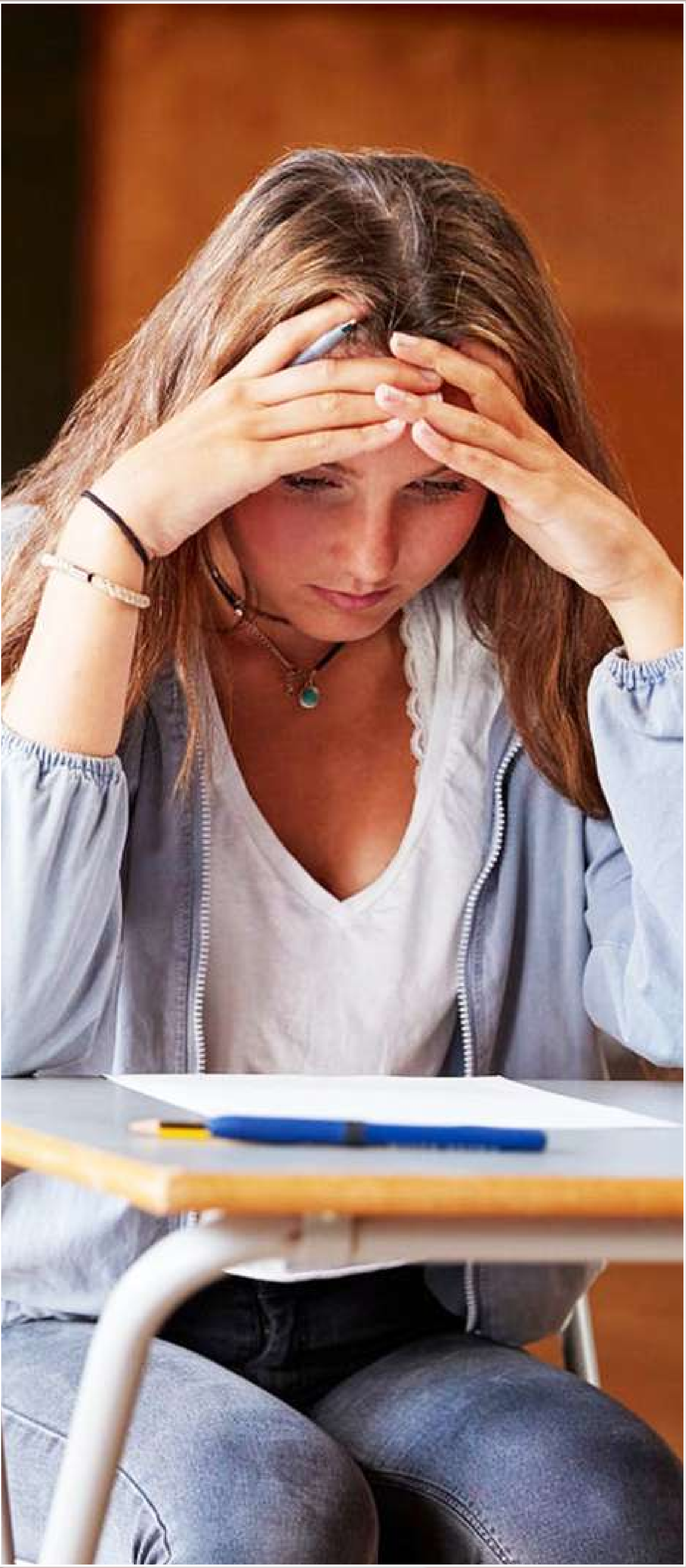

परीक्षा में सफलता का असली सूत्र

प्रो. अफरोज इकबाल

हर छात्र की सबसे बड़ी चिंता यही होती हैकृ"परीक्षा में अच्छे अंक कैसे आएँ?"

अनेक विद्यार्थी दिन–रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता। कई बार तो यह देखकर निराशा होती है कि "इतनी मेहनत करने के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिली?"

असल कारण यह है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए एक 'सही रणनीति' की आवश्यकता होती है।

गलतफ़हमीः अधिक समय = अधिक सफलता

अधिकतर छात्र यह मानते हैं कि जितना अधिक समय पढ़ाई में देंगे, उतने ही अच्छे अंक आएँगे। परंतु बिना योजना के 10 घंटे पढ़ाई करना, एक योजनाबद्ध 5 घंटे की पढ़ाई से भी कम असरदार होता है।

परीक्षा में सफलता का असली सूत्र केवल "लंबा समय" नहीं, बल्कि स्मार्ट अध्ययन और निरंतरता है।

सफलता का असली सूत्रः

1. स्पष्ट लक्ष्य

जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तैयारी बेमकसद होगी।

उदाहरणः "मुझे एसएससी की तैयारी करनी है" कहना पर्याप्त नहीं, बल्कि "छह महीने में एसएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी है" जैसा साफ़ लक्ष्य होना चाहिए।

2. सही योजना

पूरे पाठ्यक्रम को छोटे हिस्सों में बाँटें।

रोज़ का समय सारिणी बनाएँ।

पुनरावृत्ति और अभ्यास–परीक्षा को योजना का हिस्सा बनाएँ।

3. नियमित अभ्यास

सफल वही होते हैं जो रोज़ थोड़ा–थोड़ा लेकिन लगातार पढ़ते हैं।

एक दिन 10 घंटे पढ़कर अगले दो दिन आराम करने से सफलता नहीं मिलती।

4. पुनरावृत्ति और अभ्यास–परीक्षा

परीक्षा केवल याददाश्त का खेल नहीं है, बल्कि समय प्रबंधन और अभ्यास का खेल है।

जितना अधिक आप मॉडल टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न हल करेंगे, उतना ही आत्मविश्वास परीक्षा में बढ़ेगा।

5. स्वास्थ्य और संतुलन

पढ़ाई के साथ–साथ नींद, भोजन और व्यायाम का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है।

थका हुआ मस्तिष्क कभी अच्छे परिणाम नहीं दे सकता।

छात्रों की आम भूलें–

' बार–बार पाठ्यक्रम या विषय बदलना।

दूसरों की रणनीति को कॉपी करना।

केवल नोट्स बनाते रहना, लेकिन पुनरावृत्ति और अभ्यास न करना।

आत्म–संदेह में जीना।

इन भूलों से बचना ही आधी सफलता है।

मेरे अनुभव सेः

कई वर्षों तक छात्रों को पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के बाद मैंने यही पाया है कि जिन विद्यार्थियों ने यह सूत्र अपनाया, वे बार–बार सफल हुए।

उनका लक्ष्य स्पष्ट था, योजना सही थी और मेहनत निरंतर थी।

यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ:

"परीक्षा जीतने का खेल केवल किताबों का नहीं, बल्कि दिमाग़ और अनुशासन का है।

परीक्षा में सफलता का असली सूत्र हैः

स्पष्ट लक्ष्य + सही योजना + नियमित अभ्यास + पुनरावृत्ति + अनुशासन'

जो भी छात्र इन पाँच बातों को अपनाता है, उसके लिए सफलता निश्चित है।

"परीक्षा की तैयारी को सरल और प्रभावी बनाने के लिए मैं निरंतर छात्रों के साथ काम करता हूँ। सही रणनीति और छोटे–छोटे उपायों से कितने ही छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। इन विषयों पर मेरे व्याख्यान और वीडियो उपलब्ध हैं। यदि आप अपनी परीक्षा–तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल – ''करियर गाइड डॉ. अफ़रोज़ इक़बाल – आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।"'

घर की छत पर न रखें ये चीजें, आर्थिक संकट से हो जाएंगे परेशान

वास्तु शास्त्र में दिशाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में घर में रखी हर चीज वास्तु के अनुसार ही रखनी चाहिए। वरना नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर की छत पर कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए। इन चीजों के छत पर रखे होने से परिवार पर बुरा असर होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है।

घर की छत पर कूड़ा

बहुत से लोग घर की छत पर कूड़ा आदि रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा छत पर पुरानी रद्दी और कागज रखना भी अशुभ प्रभाव डालता है। इस तरह देवी लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में व्यक्ति को पैसों से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं।

ऐसे पेड़-पौधे न रखें

कई लोगों को घर की छत पर पेड़-पौधे आदि लगाना पसंद होता है। ऐसे में अगर छत पर भी पेड़-पौधे हैं, तो ध्यान रखें कि खराब पेड़-पौधे जिन पर दूध मिट्टी जमा हो गई हो, उन्हें छत पर बिल्कुल भी न रखें। आपको छत पर लगाए जाने वाले पेड़-पौधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इन चीजों को न रखें

ऐसा माना जाता है कि आपको छत पर झाड़ू, जंग लगा लोहा, टूटी हुई लकड़ी आदि चीजों को संग्रहित करने से बचना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसके अलावा छत पर रस्सियों का बंडल रखना भी वास्तु शास्त्र में अशुभ माना जाता है। इस कारण व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं।

सभार : नई दुनिया

डिसक्लेमर : 'इस लेख में दी गई जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/धार्मिक मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी।'

कुदरती तरीके से पाये एसिडिटी से राहत

आज की बिजी लाइफ में हम अक्सर अपनी डाइट और रहन–सहन का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर में कई तरह की दिक्कतें होने लगी हैं. इनमें से एक बेहद कॉमन, लेकिन परेशान करने वाली दिक्कत है 'एसिडिटी'। पेट में जब एसिड बढ़ जाता है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसमें पेट में जलन, सीने में दर्द और कभी–कभी गले में खट्टी डकार आने लगती है, जो दिनभर हमारे काम करने की क्षमता पर भी असर डालती है। ज्यादातर लोग तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके कुदरती तरीके भी हैं, जिनसे एसिडिटी से तुरंत आराम पाया जा सकता है।

एसिडिटी दूर करने के घरेलू उपाय

1. दूध और केला

आयुर्वेद के मुताबिक, जब पेट में एसिड बढ़ जाता है तो ठंडा दूध पीना एक कारगर उपाय होता है। दूध में मौजूद कैल्शियम पेट के अम्ल को कम करता है और जलन को शांत करता है। इसके साथ ही केला भी एसिडिटी में राहत देने वाला फल है क्योंकि इसमें कुदरती तत्व होते हैं जो एसिडिटी से जुड़ी पेट की परेशानियों को कम करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। केला खाने से पेट को तुरंत आराम मिलता है और जलन का अहसास कम हो जाता है।

2. जीरा और अजवाइन

इसके अलावा, आयुर्वेद ने एसिडिटी से राहत में जीरा और अजवाइन का भी बड़ा योगदान माना है। जीरा और अजवाइन दोनों ही भारतीय घरों में हाजमा सुधारने के लिए लंबे वक्त से इस्तेमाल में आते रहे हैं। जीरे को पानी में उबालकर पीने से पेट में बनने वाली गैस और एसिडिटी कम होती है, जिससे पेट हल्का महसूस होता है। अजवाइन को पानी में उबालकर या हल्का काला नमक डालकर खाने से भी डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है और पेट की मांसपेशियां आराम पाती हैं। ये दोनों उपाय न सिर्फ पेट की जलन को कम करते हैं बल्कि पाचन को भी दुरुस्त करते हैं, जिससे खाना जल्दी पचता है और एसिडिटी की समस्या कम होती है।

3. नारियल पानी

नारियल पानी भी एक शानदार कुदरती इलाज है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस रखते हैं, जिससे पेट में एसिडिटी कम होती है और जलन में राहत मिलती है।

4. सौंफ

खाने के बाद सौंफ चबाना भी एक पुराना और असरदार तरीका है जो पेट की गैस को कम करता है और हाजमे को सुधारता है। सौंफ के इस्तेमाल से भोजन जल्दी पचता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाती है।

डिसक्लेमर : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया। यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है। हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है। आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

कौसानीः
भारत का स्वीट्जरलैंड

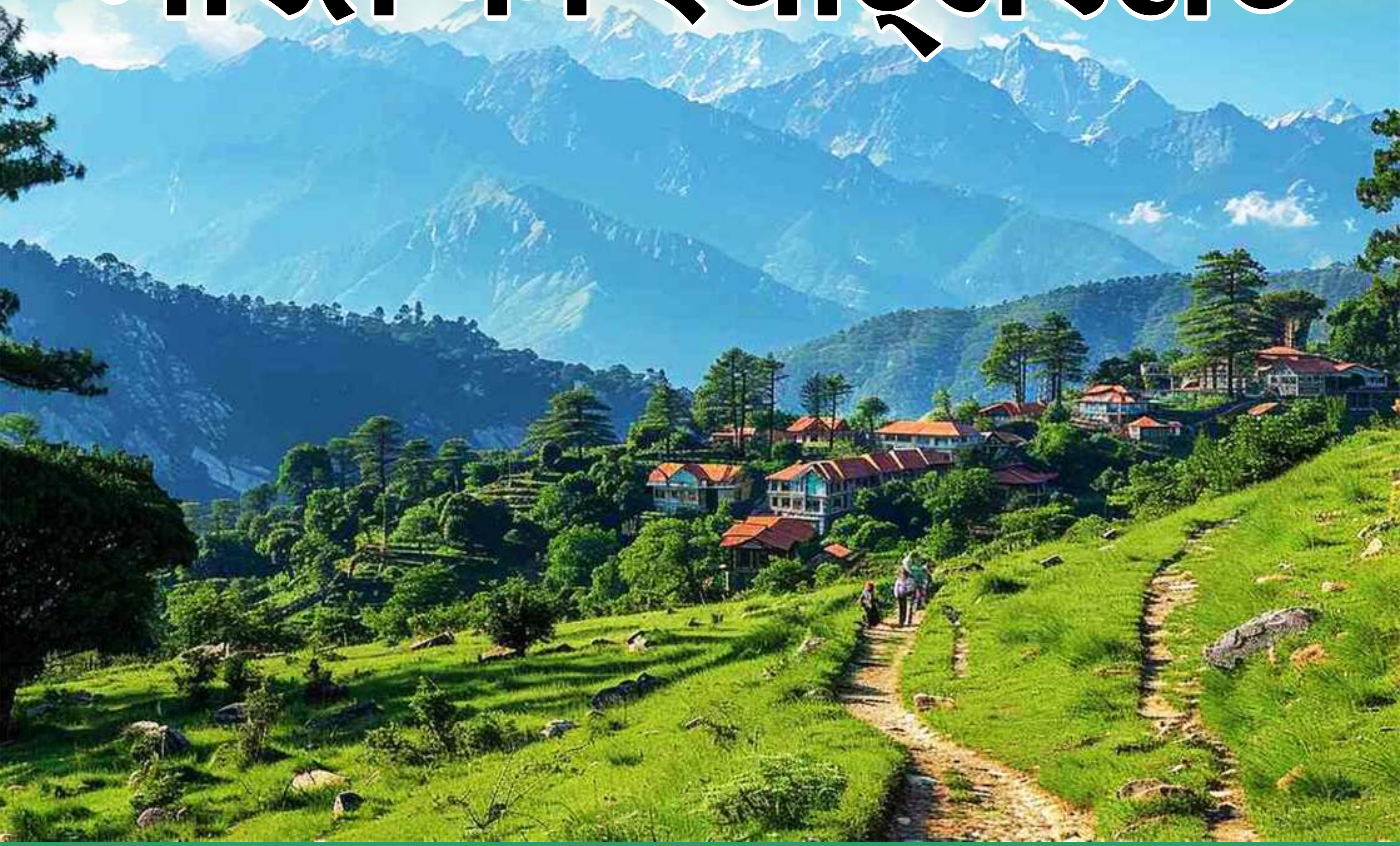

उत्तराखण्ड में बसा कौसानी एक खूबसूरत पर्वतीय पर्यटक स्थल है। विशाल हिमालय के अलावा यहां से नंदाकोट, त्रिशूल और नंदा देवी पर्वत का भव्य नजारा देखने को मिलता है। यह पर्वतीय शहर चीड़ के घने पेड़ों के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहां से सोमेश्वर, गरुड़ और बैजनाथ कत्यूरी की सुंदर घाटियों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है।

“ सुंदर धुंगा ट्रेक, पिण्डारी ग्लेशियर ट्रेक और मिलम ग्लेशियर ट्रेक का शुमार भारत के सबसे अच्छे ट्रेकिंग रुट में होता है। ”

काफी समय पहले कासौनी अल्मोड़ा जिले का हिस्सा था और वलना के नाम से जाना जाता था। उस समय अल्मोड़ा जिला कत्यूरी के राजा बैचलदेव के क्षेत्रधिकार में आता था। बाद में राजा ने इसका काफी बड़ा हिस्सा एक गुजराती ब्राह्मण श्री चंद तिवारी को दे दिया। महात्मा गांधी ने यहां की भव्यता से प्रभावित हो कर इस जगह को 'भारत का स्वीट्जरलैंड' कहा था। वर्तमान में कौसानी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और हर साल यहां पूरे विश्व से सैलानी आते हैं।

कौसानी के आस पास के स्थल

खूबसूरत पहाड़ियों और पर्वतों के अलावा कौसानी आश्रमों, मंदिरों और चाय के बगानों के लिए भी जाना जाता है। अनाशक्ति आश्रम यहां का एक प्रसिद्ध आश्रम है, जहां महात्मा गांधी कुछ दिन के लिए रुके थे। अब यह एक अध्ययन और शोध केंद्र के रूप में विकसित हो गया है, जहां रहने और खाने की भी व्यवस्था है। एक और जाना माना

आश्रम है लक्ष्मी आश्रम। इसे सरला आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस आश्रम का निर्माण 1948 में महात्मा गांधी की एक अनुयायी कैथरीन हिलमन ने करवाया था।

पिन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, रुद्रहरि महादेव मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर और बैजनाथ मंदिर कौसानी के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। समुद्र तल से 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पिन्नाथ मंदिर हिन्दू देवता भैरों को समर्पित है। शिव मंदिर सोमेश्वर शहर में पड़ता है, जो कौसानी से 11 किमी दूर है। भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने करवाया था।

इसके अलावा कौसानी प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्मभूमि भी है। यहां एक संग्राहलय भी है, जिसे सुमित्रानंदन पंथ गैलरी के नाम से जाना जाता है। इसमें इस महान कवि की कविताओं की पांडुलिपि, विभिन्न कृतियां और उन्हें दिए गए पुरस्कारों का संग्रह है। संग्राहल में हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाया जाता है और उनके सम्मान में एक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है।

जोखिम को पसंद करने वाले पर्यटक यहां ट्रेकिंग (लंबी पैदल यात्रा) और रॉक क्लाइंबिंग (चट्टानों की चढ़ाई) का आनंद ले सकते हैं। सुंदर धुंगा ट्रेक, पिण्डारी ग्लेशियर ट्रेक और मिलम ग्लेशियर ट्रेक का शुमार भारत के सबसे अच्छे ट्रेकिंग रूट में होता है। यह जगह हिंदू धर्म के एक त्योहार मकर संक्रांति को मनाने के लिए भी जाना जाता है, जिसे यहां उत्तरायनी कहते हैं।

कौसानी कैसे जाएं

देश के अलग–अलग हिस्सों से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से कौसानी आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है। यह भारत के अन्य शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। कौसानी का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम लखनऊ, दिल्ली और हावड़ा जैसे शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। कौसानी बस स्टेशन भी कई शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है।

कौसानी जाने का सबसे अच्छा समय

ज्यादातर पर्यटक अप्रैल से जून के बीच में कौसानी घूमने आते हैं, क्योंकि इस समय यहां का मौसम काफी खुशगवार रहता है।

कौसानी चाय बगान

कौसानी चाय बगान कौसानी से 5 किमी दूर बागेश्वर रोड पर स्थित है। यह बगान 21 भागों में बंटा हुआ है और 208 हेक्टियर में फैला हुआ है। उत्तराखण्ड की मशहूर 'गिरियास टी' का उत्पादन यहीं होता है। इसके अलावा जैविक चाय का भी उत्पादन किया जाता है और इस खुशबूदार चाय को संयुक्त राष्ट्र, जर्मनी, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में निर्यात किया जाता है।

सभार : nativeplanet

मैं टाईम विटनेस की सदस्यता ले रहा/रही हूं।

नाम – श्री/श्रीमती/कुमारी...जन्म तिथि...
पता...
....राज्य...
फोन (निवास)..................................मोबाईल..ई–मेल..
कृपया Time Witness के नाम का डी.डी. या चेक नं................................तिथि.......................प्राप्त करें।
बैंक का नाम...

कृपया इस फार्म को भरकर डी.डी. या चेक के साथ हमे इस पते पर भेंजे।

टाईम विटनेस, मासिक पत्रिका

नियर रिवरेन पब्लिक स्कूल, ब्राह्मणवाला, निरंजनपुर, देहरादून– 248171

7409293012, 7078188479

अवधि	अंको की संख्या	कवर मूल्य	बचत	सब्सक्रिप्शन मूल्य
1 वर्ष	12	150.00	30.00	180
2 वर्ष	24	290.00	70.00	360
3 वर्ष	36	430.00	110.00	540
4 वर्ष	48	520.00	200.00	720

नियम व शर्तें

1. यह योजना केवल भारत में ही मान्य है।

2. पत्रिका साधारण डाक द्वारा भेजी जाएगी तथा डाक गुम हो जाने पर जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी। सूचना प्राप्त होने पर यदि वह अंक उपलब्ध रहता है तो पुनः निशुल्क प्रेषित कर दिया जायेगा।,

3. कूरियर रजि. डाक से मंगवाने के लिए ग्राहक का कूरियर रजि. डाक खर्च अतिरिक्त वहन करना होगा।

4 सभी विवादों का निपटारा देहरादून (उत्तराखण्ड) न्यायालय के अधीन होगा।

!! ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय नमः !!
ESTD.1923
SRI KAILSWARI COLOUR MATCH WORKS
नकली दुकानदारों से सावधान
पटाखों के होल सेल विक्रेता
PAWAN ANAND
ANAND Fire Works
पटाखे ही पटाखे
43, Dhamawala Bazar, Near Masjid, Dehradun
Saharanpur Road, Opp. MDDA, Dehradun
M.: 9837374752, 9756553790, 0135-2711681

समस्त प्रदेश व देशवासियों को
दीपावली
गोवर्धन पूजा
व भैया दूज
की हार्दिक
शुभकामनाएं
आर.ए. खान
निदेशक
प्रयाग आई.ए.एस अकादमी

KOHINOOR ART JEWELLERS
SINCE 1999
MAJRA, DEHRADUN
Kohinoor
Art Jewellers
EK Anmol Rishta...
"गोल्ड ज्वैलरी खरीदें और पाएँ मौका स्कूटी जीतने का"
KOHINOOR FESTIVE OFFER
100% Exchange Offer
पुराने जेवर बदलने पर कोई कटौती नहीं
"Assured Gift with Every Purchase"
10% TO 40% off
(Maximum Discount)
Making Charges
GOLD JEWELLERY
50% off
Making Charges on
SILVER JEWELLERY
75% off
Making Charges on
DIAMOND JEWELLERY
ऑफर अवधिः
20 सितम्बर से
31 दिसम्बर 2025
68-MAJRA SAHARANPUR ROAD DEHRADUN (UK) MOB.-8755655529, 7830677750, 9837359716

न्यूरो सर्जरी की
विशेष सुविधा

- ब्रेन ट्यूमर • मिर्गी • रीढ़ की हड्डी की चोट
- दिमाग में खून की नस का फटना
- सिर व रीढ़ की हड्डी की जन्मजात विकृति
- रीढ़ की हड्डी की टी. बी., कैंसर व स्लिप डिस्क
- दिमाग में पानी भरना
- सिर की चोट

नि:शुल्क*
मोतियाबिंद का ऑपरेशन
नियम एवं शर्तें लागू

नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र
की सुविधा भी उपलब्ध है

नि:शुल्क*
नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी

24/7 24 घंटे सेवाएं

- ☑ ब्लड बैंक सेवाएं
- ☑ आपातकालीन सेवाएं
- ☑ जाँच प्रयोगशाला (लैब)
- ☑ फार्मेसी सेवाएं (दवाइयाँ)

• ई.एस.आई.सी. • सी.जी.एच.एस. • एस.जी.एच.एस.
• आयुष्मान कार्ड • टी.पी.ए. के अंतर्गत कैशलेश उपचार एवं सर्जरी की सुविधा

▼ सुविधाएँ

• फ्रैक्चर • हाथ की सर्जरी • स्पोर्ट्स इंजरीस तथा लिगामेंट की सर्जरी • एम.आर.आई. • घुटने, कूल्हे एवं जोड़ प्रत्यारोपण (बदलने) की सुविधा • सी. टी. स्कैन • अल्ट्रासाउंड • घुटने एवं कंधे की दूरबीन द्वारा जाँच एवं सर्जरी (आर्थ्रोस्कोपी) • डिजिटल एक्स-रे • जनरल सर्जन • दन्त रोग विशेषज्ञ • नेत्र रोग विशेषज्ञ • फिजियोथेरेपी • कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ • हर्निया तथा हाइड्रोसील का ऑपरेशन • हड्डी रोग विशेषज्ञ • बाल रोग • गुर्दे एवं पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन • जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ • त्वचा रोग विशेषज्ञ • स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ • एंडोस्कोपी (दूरबीन द्वारा जाँच) • मनोरोग चिकित्सक • नशा मुक्ति एवं पुनर्वास • नार्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी • लैप्रोस्कोपी (की- होल सर्जरी / मिनिमल इनवेसिव सर्जरी) केंद्र • स्लिप डिस्क का इलाज • शुगर एवं बी.पी. का इलाज • छाती रोग विशेषज्ञ • सांस फूलने का इलाज • टी. बी. का इलाज

Helpline Number
+91 8194007026

info@gbcm.in | www.gbcm.in
subhartihospitalddn | gbcm_subhartihospital
सुभारतीपुरम - फेज 2, एन.एच. 72, झाझरा, चकराता रोड़, देहरादून - 248007, उत्तराखण्ड

आपका अपना डॉ॰ के.के.बी.एम.
सुभारती अस्पताल
झाझरा, देहरादून

GBCM